

NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

घरेलू छत सौर योजना में सुधार की
आवश्यकता

www.nextias.com

घरेलू छत सौर योजना में सुधार की आवश्यकता

सन्दर्भ

- हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PMSGMBY) जिसका उद्देश्य पूरे भारत में छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों को अपनाने को बढ़ावा देना है, इसकी आशाजनक शुरुआत के बावजूद इसकी क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए इसमें सुधार की आवश्यकता है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PMSGMBY): उद्देश्य और कार्यान्वयन

- यह आवासीय घरों में सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक परिवर्तनकारी पहल है।
- इसका उद्देश्य छत पर सौर पैनल लगाकर घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है।
- इसका पर्याप्त परिव्यय ₹75,021 करोड़ है और इसे वित्तीय वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है।
- इसका लक्ष्य मार्च 2027 तक 10 मिलियन छोटे छत पर सौर संयंत्र स्थापित करना है, जिसमें 3 किलोवाट तक की क्षमता के लिए ₹30,000 से ₹48,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- कार्यान्वयन की देखरेख राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (NPIA) द्वारा की जाती है, जबकि राज्य कार्यान्वयन एजेंसियाँ (SIA) राज्य स्तर पर निष्पादन का प्रबंधन करती हैं।

प्रमुख विशेषताएँ

- सब्सिडी संरचना:** यह योजना 2 किलोवाट क्षमता तक की प्रणालियों के लिए सौर इकाई लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच की प्रणालियों के लिए 40% सब्सिडी प्रदान करती है।
 - सब्सिडी 3 किलोवाट क्षमता तक सीमित है, जो अधिकतम 78,000 रुपये की सब्सिडी है।
- पात्रता:** आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, सौर पैनल स्थापना के लिए उपयुक्त छत वाला घर होना चाहिए, उसके पास वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए और सौर पैनलों के लिए किसी अन्य सब्सिडी का लाभ नहीं उठाना चाहिए।
- आवेदन प्रक्रिया:** इच्छुक उपभोक्ताओं को अपने राज्य और बिजली वितरण कंपनी का चयन करके राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
 - पोर्टल प्रासंगिक जानकारी, जैसे सिस्टम का आकार, लाभ कैलकुलेटर और विक्रेता रेटिंग प्रदान करके परिवारों की सहायता करता है।
- विक्रेता पंजीकरण:** विक्रेता आवेदन और प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करके संबंधित DISCOMs के साथ पंजीकरण कर सकते हैं।
 - यह उपभोक्ताओं के लिए पंजीकृत विक्रेताओं में से चुनने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।

PMSGMBY की प्रगति

- तेजी से स्थापना:** अपने लॉन्च के बाद से, PMSGMBY ने उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, पहले नौ महीनों के अंदर 6.3 लाख से अधिक स्थापनाएँ पूरी की गई हैं।
 - यह योजना की शुरुआत से पहले की अवधि की तुलना में मासिक स्थापनाओं में दस गुना वृद्धि दर्शाता है।
- राज्य-स्तरीय सफलता:** गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने सुदृढ़ बुनियादी ढाँचे एवं प्रभावी हितधारक सहयोग के कारण असाधारण प्रगति दिखाई है।

- **सरलीकृत प्रक्रियाएँ:** अधिकांश DISCOM ने 10kW से कम की प्रणालियों के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अनुमोदन को माफ कर दिया है और अपनी प्रक्रियाओं को डिजिटल कर दिया है, जिससे रूफटॉप सोलर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल पर केवल पाँच मिनट में आवेदन दाखिल किए जा सकते हैं।
- **विक्रेता और कार्यबल विकास:** लगभग 9,000 विक्रेताओं को सक्रिय किया गया है, और क्षमता निर्माण पहलों ने उच्च गुणवत्ता वाली स्थापना एवं सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए 40,000 कर्मियों को प्रशिक्षित किया है।
 - अगले आठ महीनों में अतिरिक्त 2 लाख तकनीशियनों को प्रशिक्षित किए जाने की संभावना है।

PMSGMBY की चुनौतियाँ और सुधार

- **बुनियादी ढांचा और विनियामक बाधाएँ:** प्रारंभिक कार्यान्वयन में DISCOMs के लिए बिजली लोड क्षमता बढ़ाने और विनियामक बाधाओं को कम करने की आवश्यकता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
 - 10kW तक की प्रणालियों के लिए तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट (TFR) को माफ करके और समय पर निरीक्षण एवं सब्सिडी जारी करना सुनिश्चित करके इन मुद्दों को संबोधित किया गया।
- **वित्तीय और भुगतान सुरक्षा:** इस योजना ने भुगतान सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिए ₹100 करोड़ का कोष स्थापित किया है, लेकिन इस कोष को बनाए रखना और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है।
- **तकनीकी और परिचालन संबंधी मुद्दे:** नेट मीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करना और रूफटॉप इंस्टॉलेशन से संबंधित तकनीकी मुद्दों का समाधान करना निरंतर चुनौतियाँ हैं।
 - इंस्टॉलेशन की गुणवत्ता और दक्षता बनाए रखने के लिए DISCOM इंजीनियरों और तकनीशियनों के लिए निरंतर प्रशिक्षण और सहायता आवश्यक है।
- **गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** पर्याप्त निगरानी के बिना 10,000 से अधिक सेवा प्रदाताओं के संचालन के कारण घटिया इंस्टॉलेशन का जोखिम है।
 - रूफटॉप सोलर सिस्टम की दीर्घकालिक विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त गुणवत्ता एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित करना आवश्यक है।
- **क्षेत्रीय असंतुलन:** अपनी शुरुआत से लेकर अब तक, इस योजना ने 638,352 स्थापनाओं की सुविधा प्रदान की है, जिससे लगभग 2 गीगावाट सौर क्षमता का योगदान हुआ है।
 - हालाँकि, इन स्थापनाओं का वितरण बहुत अधिक विषम है, अकेले गुजरात और महाराष्ट्र में कुल का 65% से अधिक हिस्सा है।
- **पंजीकरण, आवेदन और वास्तविक स्थापनाओं में अंतराल:** 14.5 मिलियन पंजीकरणों में से, केवल 2.65 मिलियन आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं, और केवल 0.68 मिलियन स्थापनाएँ पूरी हुई हैं।
 - यह कार्यान्वयन प्रक्रिया में अक्षमताओं का सुझाव देता है, जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।
- **कुशल कार्यबल की कमी:** वर्तमान में, इस क्षेत्र में प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी है। यह अंतर योजना के क्रियान्वयन को धीमा कर सकता है, क्योंकि घरों और व्यवसायों को अपने सौर पैनल स्थापित करने एवं चालू करने में देरी का सामना करना पड़ सकता है।
- **नौकरशाही और तार्किक चुनौतियाँ:** आवेदन प्रक्रिया को नेविगेट करना, आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना और समय पर स्थापना सुनिश्चित करना कई उपभोक्ताओं के लिए बोझिल हो सकता है।
 - यह संभावित अपनाने वालों को हतोत्साहित कर सकता है और योजना की समग्र प्रगति को धीमा कर सकता है।

- **उपभोक्ता जागरूकता और भागीदारी:** प्रगति के बावजूद, जनसंख्या के व्यापक वर्ग के बीच जागरूकता बढ़ाना और भागीदारी को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। कई संभावित लाभार्थी अभी भी योजना के लाभों और सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया से अनजान हैं।

निष्कर्ष और आगे की राह

- इस योजना का मूल उद्देश्य अत्यंत गरीब लोगों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना था, लेकिन वर्तमान कार्यान्वयन इस जनसांख्यिकीय वर्ग तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पा रहा है।
- माना जाता है कि प्रतिष्ठानों का औसत टिकट आकार 3 किलोवाट से अधिक है, जो इच्छित लाभार्थियों के लिए वहनीय नहीं हो सकता है।
 - यह सुनिश्चित करना कि सब्सिडी और सहायता उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें वास्तव में इसकी ज़रूरत है, योजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।
- कार्यान्वयन प्रक्रिया को परिष्कृत करके, समान वितरण सुनिश्चित करके, गुणवत्ता मानकों को स्थापित करके और सही लाभार्थियों को लक्षित करके, यह योजना भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है और लाखों घरों को स्थायी ऊर्जा समाधान प्रदान कर सकती है।

Source: BL

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत में वर्तमान घरेलू छत सौर योजना को व्यापक रूप से अपनाने और इसके संभावित लाभों को अधिकतम करने के लिए महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है?